

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. GAC-21-35/2017-CDN

Dated 23 Oct., 2017

ENDORSEMENT

Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, New Delhi has issued O.Ms regarding Implementation of recommendation of the Seventh Pay Commission on Dress Allowance. The said O.Ms No. 14/4/2015-JCA- 2 dated 31.08.2017 and 01.09.2017 have been uploaded on the ICAR website www.icar.org.in and e-office for information.

(Ajai Verma) Under Secretary (GAC)

Distribution:-

- 1. Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/NRCs/ Project Coordinators.
- 2. PSO to DG, ICAR/ PPS to Secretary, ICAR/ PPS to FA, DARE/ICAR
- 3. All Officers/Sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB I & II/NASC
- 4. Media Unit for placing on the ICAR website.
- 5. Guard file/Spare copies

F. No. 14/4/2015-JCA 2 Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training) Establishment (JCA-2) Section

North Block, New Delhi Dated: August 31, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of recommendation of the Seventh Central Pay Commission on Dress Allowance - regarding.

The undersigned is directed to state that in pursuance of the decisions taken by the Government on the recommendations of Seventh Central Pay Commission, and in supersession of the existing orders relating to admissibility of Uniform Allowance/ Washing allowance/ Stitching Charges /Shoe allowance, etc to common categories of Group 'C' and erstwhile Group 'D' employees of various Ministries/Departments, including attached/ subordinate offices, who are supplied uniform and are required to wear them regularly, they shall be paid Dress Allowance at the rate of Rs. 5000/- per year.

- The Uniform Allowance/Washing Allowance/Stitching Charges/Shoe Allowance, 2. etc. have been subsumed in Dress Allowance.
- The categories of Staff who were earlier being provided uniforms if any, shall henceforth not be provided with uniform.
- Allowance related to maintenance and washing of uniform is subsumed under Dress Allowance, and will not be payable separately.
- The amount of Dress Allowance shall be credited to the salary of employees directly once a year in the month of July.
- The rate of Dress Allowance shall be, as mentioned in para-1 above, Rs.5000/-6. per year. The rate of Dress Allowance shall go up by 25% every time the Dearness Allowance rises by 50%.
- This allowance covers only the basic uniform of the employees. Any special clothing will continue to be provided by the concerned Ministry as per existing norms.
- 8. This order shall take effect from 1st July, 2017.

Hindi version will follow.

Deputy Secretary (JCA)

Tel. No. 2309 2982

फा. सं. 14/4/2015-जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

कृषिए (वेयर) एवं न.नि. (म.कृ.अनु.प.) का कार्यालय Onice of Secy (DARE) & DG (ICAR)

aOffice Dy. No. 1844o8../R Date....15.-.09-1.7.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : र सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वर्दी भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश ह्आ है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समूह 'ग' श्रेणी और पूर्ववर्ती 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्दी प्रदान की जाती है और जिनके लिए उसे नियमित रूप से पहनना आवश्यक होता है, को वर्दी भता/धुलाई भता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) भता इत्यादि की देयता के संबंध में मौजूदा आदेशों के अधिक्रमण करते हुए उन्हें 5000/-रु. प्रति वर्ष की दर से वर्दी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

- वर्दी भता/धुलाई भता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) प्रभार इत्यादि को वर्दी भत्ते में शामिल कर दिया गया है।
- जिन श्रेणी के कर्मचारियों को पहले किसी प्रकार की वर्दी प्रदान की जा रही थी उन्हें अब से वर्दी प्रदान नहीं की जाएगी।
- वर्दी के रख-रखाव और इसकी धुलाई से संबंधित भन्ने, वर्दी भन्ने में शामिल कर दिए गए हैं और अलग से इनका भ्गतान नहीं किया जाएगा।
- 5. वर्दी भते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दी जाएगी।
- जैसा कि ऊपर पैरा-1 में उल्लिखित है, वर्दी भत्ते की दर 5000/- रू. प्रति वर्ष होगी। जब महंगाई भते में 50% की वृद्धि होगी तब वर्दी भते की दर में हर बार 25% की वृद्धि हो जाएगी।

इस भते में कर्मचारियों की मूल वर्दी ही शामिल है। अन्य, विशेष वस्त्र संबंधित मंत्रालय द्रव्यरा

Aggi Calture Res & Education M/o Aggiculture

मौजूदा मापदंडों के अन्सार प्रदान किए जाते रहेंगे।

यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।

(डी. के. सेनग्प्ता)

उप सचिव (जेसीए)

दूरभाष : 23092982

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग